\mathcal{O}_{j}



श्र साधारए

EXTRAORDINARY

भाग 1---श्रण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई विल्ली, जुकबार, फरवरी 28, 1969/फाल्गुम 9, 1890

No. 28]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1969/PHALGUNA 9, 1890

इस भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भ्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

> बजट 1969-70 उप-प्रधान मंत्री श्रौर वित्त मंत्री का भाषण 28 फरवरी 1969

महोवय,

मैं चौथी पंचवर्षीय आयोजना की श्रवधि का पहला बजट पेग कर रहा हूं। इस काम में मेरी कठिनाई यह है कि आयोजना का प्रलेख श्रभी माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। इस समय तो मैं केवल सुक्षधार के रूप में आप के सामने उपस्थित हुआ हूं जिसका काम नाटक प्रारम्भ होने से पहले कुछ समय के लिये रंगमंच पर श्राकर नाटक में दर्शकों की रुचि बढ़ाना होता है। मैं श्राशा करता हूं कि माननीय सदस्य कम से कम इस कारण निराश नहीं होंगे कि मेरा भाषण छेट है।

प्रस्ता अना

- 2. चालू वर्ष, जो ग्रब समाप्त हो रहा है, भारतीय ग्रर्थ-व्यवस्था के लिये ग्रच्छा वर्ष साबित हुमा है। अपने पिछले बजट-भाषण में मैंने यह ग्राशा प्रकट की थी कि यदि सही नीतियां श्रपनायी जाएँ तो 1968-69 का वर्ष पून-रुत्थान का वर्ष हो सकेगा। यह श्राशा बहुत हद तक पूरी हो गयी है । इस वर्ष भी, पिछले वर्ष की तरह, श्रन्न की फसल सन्तोषजनक होने की उम्मीद है। ग्रौद्योगिक पुनरुत्यान के साफ चिह्न दिखाई दे रहे हैं। ग्रौद्योगिक उत्पादन में भनुमानतः लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिवहन का काम श्रीर व्यापार दोनों फिर बढ़ें हैं। बिजली या कच्चे माल की ज्यादा कमी नहीं हुई है। मुल्यों का सामान्य स्तर इस समय े पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है। निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। ग्रायोजनाग्रों के दौरान जो प्रयत्न किये गये हैं उनके कारण श्रब देश में ही ऐसी बहत-सी चीजें तैयार को जा रही हैं जो पहले विदेशों से मंगायी जाती थीं। यद्यपि 1967-68 की श्रवेक्षा ऋण-शोधन का भार श्रिधिक है भीर विदेशी सहायता का उपयोग कुछ कम हम्रा है, तो भी सम्भवतः चाल वर्ष में हमारी विदेशी मद्रा की रकम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार, कृषि के काम में नयी चेतना मा गयी है, उद्योगों का पुनरुत्थान हो रहा है, मत्य किर स्थिर हो गये हैं और हम स्वावलम्बन कि लक्ष्य की श्रोर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा स्थिति के ग्रन्ध र पर हम श्रब श्रगली वर्षीय श्रायोजना का काम काफी ब्रात्मविश्वास के साथ शरू कर सकते हैं। फिर भी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण ग्रपनी इच्छा के श्रनसार तूरन्त काम करने का हमारा वायरा बहुत कुछ सीमित हो जाता है।
 - 3. यद्यिप अन्न को पैदाबार बढ़ गई है, तो भी देश की बढ़ती हुई भ्राबादी क लिये धन्न का सन्तोषजनक प्रबंध करने के लिये हमें भ्रभी बहुत प्रयत्न करना है। कृषिजन्य कच्छे माल भ्रौर भ्रम का आयात श्रब भी काफी हो रहा है। इसलिये हमारे सीमित साधनों से कृषि में, जिसके श्रन्तगंत श्रनुसन्धान, रासायनिक खाद श्रौर पानी जैसी खेती के लिये धावश्यक चींजे श्रौर किसानों को ऋत्य देने तथा धनाज के संग्रह की सुविधाएं भी श्राती ह पूंजी लगाने की प्रथम श्रावश्यकता है। इतनी श्रावश्यक ता केवल परिवार—नियोजन के सम्बन्ध में है।
 - 4. पूंजीगत माल बनाने के उद्योग-धन्धों का देश में काफी विकास हो चुका है। इसलिये प्रिषक निवेश करना ग्रावश्यक ग्रीर साथ ही सम्भव भी हो गया है। पर अनुचित मूल्य-वृद्धि हुए बिना निवेश का बढ़ते रहना इसी ग्राधार पर सम्भव है कि ग्रान खपत की जरूरी चीजों का उत्पादन बढ़ता रहे। इसके लिये यह जरुरी है कि कृषि की उत्पादकता के साथ साथ उपभोक्ता- यस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योग-धन्धों में भी कुशलता ग्रीर उत्पादन-अमता ज्यादा हो। इन उद्योग-धन्धों की ग्रोर ध्यान देना इसलिये विशेष रूप से ग्रावश्यक है कि एसा करने से उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रेरणा मिलती है ग्रीर सरकार की ग्रामदनी भी बढ़ती है।

- 5. इस वर्ष हम राष्ट्र-पिता की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं ग्रौर हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ग्राधिक विकास का ग्रन्तिम ध्येय कई बांउनीय सामाजिक लक्ष्य प्रान्त करना है। इसलिये बुनियादी सुविधान्नों, जैसे पीने के पानी की सुविधा, शिक्षा, विकित्सा-सहायता श्रौर काम करने के श्रवसर के सम्बन्ध में तथा वस्तुत: सामान्य समता की बढ़ती हुई मान्ना के सम्बन्ध में, जा समाजवादी समाज का श्राधार है, लोगों की जो स्वाभाविक श्राकाक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना भी हमारे लिये ग्रावश्यक है।
- 6 बैदेशिक क्षेत्र में जो मुधार हुआ है वह उतना ही उल्लेखनीय है जितना बांछनीय है; फिर भी, निर्यात से होने वाली हमारी धामदनी इस समय धायत—सम्बन्धी हमारी वर्तमान धावस्थकता का केवल दो तिहाई भाग है। इसलिये निर्यात बढ़ाने धौर विदेशों से मांगायी जाने वाली चीजों का देश में उत्पादन करने के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त होकर बैठे नहीं रह सकते। 1965–66 धौर 1966–67 की ध्रसाधारण परिस्थितियों के कारण ध्रर्थ —व्यवस्था में बचत की दर कम हो गयी है। साधन जुटाने के बहुत प्रयत्न किये जाने धौर व्यय पर बहुत नियन्द्रण रखे जाने पर भी पिछले कुछ वर्षों में सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गयी है।
- 7. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अगली पंचवर्षीय श्रायोजना की श्रविध में विस्तृत क्षेत्र में फिर प्रगति शुरू करने के लिए देश की सामान्य ग्राधिक स्थिति श्रनुकूल है। पर, खपत श्रीर निवेश के बीच, साधनों श्रीर परिव्यय के बीच, श्राधिक विकास श्रीर वैदेशिक भुगतान-क्षमता के बीच श्रीर वस्तुत: बड़े सामाजिक लक्ष्यों श्रीर विशुद्ध श्राधिक विचारों के बीच ठीक ठीक सन्तुलन बनाये रखने की भी श्रावश्यकता है। माननीय सदस्य श्रव यह देखेंगे कि प्रायः श्राधिक योजना बनाने वालों की गिनती सरकस में रस्सी पर चलकर तरह तरह के करतब दिखाने वालों की कला के सर्वोत्तम निवर्शकों में क्यों की जाती है।

1968-69 के संशोधित श्रनुमान

- 8. मैंने वर्तमान श्राधिक स्थिति की संक्षेप में चर्चा की है श्रीर थोड़े में यह भी बता विया है कि भविष्य में कौन से कार्य किये जाने हैं। मैं श्राशा करता हूं कि ऐसा करते हुए मैंने योजना-श्रायोग के श्रिषकार क्षेत्र में दखल नहीं विया है। श्रव मुझे ज्यादा दुनियावी बातों का जिल करना है जो वित्त मन्त्रियों के भाग्य में बवा होता है। 1968–69 के संशोधित श्रनुमानों के श्रनुसार, सीमा-शुक्क-राजस्व में, पिछले फरवरी मास में प्रस्तुत किये गये श्रनुमानों की तुलना में, 94 करोड़ रुपये की कमी होगी। इसके विपरीत, उत्पादनशुक्कों और श्रायकर से 54 करोड़ रुपया श्रिषक प्राप्त होने की श्राशा है। कर से भिन्न राजस्य को जोड़ने पर, ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि केन्द्र को प्राप्त होने वाले कुल राजस्य में 11 करोड़ रुपये की ही कमी होगी जब कि 2760 करोड़ रुपये की वसूली प्रत्याद्यित थी।
- 9. राजस्व-लाते का व्यय 2629 करोड़ रुपये के बजट-श्रनुमान से सम्भवतः 116 करोड़ रुपया बढ़ जायगा । इस वृद्धि का लगभग श्राधा भाग हिसाब-किताब में किये जाने नाले परिवर्तनों के

कारण हुआ है श्रीर वह भी पूंजी खाते के उतने ही लाभ से प्रतिसन्तुलित हो जाता है। 49 करोड़ रुपये के श्रीर व्यय का कारण राजस्व-खाते का रक्षा-सम्बन्धी श्रिषक व्यय है। इस अधिक व्यय के ये कारण हैं—
कुछ श्रीणयों के रक्षा-सेवा कर्मचारियों के भत्तों में वर्ष के दौरान की गयी वृद्धि; मंहगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया था; महगाई भत्ते का कुछ भाग वेतन में मिला देने का हाल का फैसला; श्रीर वर्तमान श्रांडरों के श्राधार पर सामान का अधिक शी श्रता से प्राप्त होना। पूंजी खाते में, रक्षा-सम्बन्धी व्यय में 13 करोड़ रुपये की कमी हुई है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि यदि रक्षा-सम्बन्धी व्यय में दुई को भौर केवल हिसाब-किताब में दिखाये जाने वाले व्यय को छोड़ दिया जाय, तो राजस्व-खाते का व्यय वजट-श्रनुमान की श्रपेक्षा एक प्रतिशत से भी कम बढ़ा है।

- 10. पूंजी-खाते में श्रीषक परिवर्तन हुए हैं। वास्तिवक विदेशी सहायता में 121 करोड़ रुपये की श्रीर पी० एल० 480 सम्बन्धी तथा दूसरी श्रश्न-सहायता में 43 करोड़ रुपये की कमी होगी। यह कमी कुछ हद तक इन बातों से प्रतिसन्तुलित हो जायगी— बाजार-ऋणों में होने वाली वृद्धि में श्रश्न और रासायनिक खाद की खरीद ग्रादि के लिए कि जाने वाली व्यवस्था में कमी और श्रायोजना-सम्बन्धी परिव्यय में कुछ कमी। दूसरी मधों के श्रन्तर्गत भी बहुत-से परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण, कुल मिलाकर, साधनों सम्बन्धी स्थित में सुधार हुआ है।
- 11. कुल मिलाकर, श्रव यह अनुमान है कि इस वर्ष वजट-सम्बन्धी कमी, बजट अनुमान के 290 करोड़ रुपये के मुकाबले, 260 करोड़ रुपया होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य घाटे की विस-व्यवस्था में हुए इस 10 प्रतिशत के परिवर्तन को इस बात का सबूत नहीं मानेंगे कि मैंने बजट-अनुमान बहुत कम लगाये थे।

1969-70 के यजट-प्रतुमान

- 12. अब मैं 1969-70 के बजट-अनुमानों की चर्चा करता हूं। मैंने यह अनुमान लगाया है कि करों की वर्तमान वरों के अनुसार केन्द्र को कुल मिला कर 151 करोड़ रुपया अधिक राजस्व आप्त होगा। मेरा अनुमान है कि सीमा-शुल्व-आप्तियों में और कमी हो जायगी, अर्थात ये आप्तियां 1969-70 म 426 करोड़ रुपया ही होंगी जबिक इस वर्ष य 445 करोड़ रुपया है। इस कमी का आधार यह अनुमान है कि जहां अस से भिन्न वस्तुओं के कुल आयात में कुछ वृद्धि होगी वहां पेट्रोलियम-पदार्थों जैसी उन वस्तुओं का आयात बहुत कम हो जायगा जिन पर शुल्क की अधिक ऊंची दरें लगी हुई हैं। अनुमान है कि केन्त्रीय उत्पादन-शुल्कों से होने वाली आप्ति में 101 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। निगम-कर और आयकर से सम्भवत: 675 करोड़ रुपया आप्त होगा जब कि इस वर्ष उनसे 660 करोड़ रुपया मिलेगा। कर से भिन्न राजस्य में भी अनुमानत: 50 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।
- 13. पर राजस्य में होते वाली वृद्धि से राजस्य खाते के ध्यय में धिषक वृद्धि होगी। राजस्य खाते के रक्षा-सम्बन्धी ध्यय में 42 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। हिसाब-किताय में किये जानेवाले कुछ समा-योजनों को छोड़ विया जाय, तो आयोजना-ध्यय से भिन्न असैनिक ध्यय में 142 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसमें से 41 करोड़ रुपये की रकम ब्याज-प्रभारों की है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को 36 करोड़ रुपये की और रकम हस्तान्तरित करना आवश्यक हो गया है। आयोजना गत जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनसे सम्बन्धित वचन-बद्ध ध्यय में लगभग 35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों पर किये जाने वाले ध्यय में लगभग 35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों पर किये जाने वाले ध्यय में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। शेष वृद्धि प्रशासनिक सेवाओं, कर-संग्रह और पड़ोसी वेशों की सहायता समेत कई विविध मदौँ के अन्तर्गत हुई है। विस्तृत विवरण, हमेशा की तरह, ब्यास्थाएमक ज्ञापन में दिया गया है।

- 14. पूंजी खाते के सम्बन्ध में यह अनुमान है कि बाजार ऋणों से अगले वर्ष 106 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम प्राप्त होगी जब कि इस वर्ष 81 करोड़ रुपये की रकम आप्त हुई हैं। छोटी बचतें 135 करोड़ रुपया आंकी गयी हैं—अर्थात चालू वर्ष की अपेका 10 करोड़ रुपया अधिक । पर इस वृद्धि का लगभग वो तिहाई हिस्सा राज्यों को मिलेगा । बोक भविष्य निधि से इस वर्ष के 2 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष सम्भवतः 5 करोड़ रुपया मिलेगा । दूसरी और अनिवार्य जमा की किसी समय प्रसिद्ध किन्तु अब प्रायः विस्मृत बोखना का प्रवर्तक होने के नाते में 1963-64 में करायी गयी जमा की वापसी के लिए 25 करोड़ रुपये की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूं।
- 15. पी॰ एल॰ 480 सम्बन्धी धौर दूसरी छन्न सहायता को छोड़ देने पर, वास्त-विक विदेशी सहायता में 1969-70 में सम्भवतः कुछ वृद्धि होगी । इस वर्ष इस सहायता की रकम 459 करोड़ रुपया है; अगले वर्ष वह अनुमानतः 467 करोड़ रुपया हो जायगी । पुकाये जाने वाले ऋणों की रकम बढ़ जायगी, पर हमारा धनुमान है कि सहायता की प्राप्ति भी पुख्यतः इस कारण बढ़ेगी कि धन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने किर सहायता देना शुरू कर दिया है ।
- 16. दिसम्बर 1968 में हमने 23 लाख मैट्रिक टन मन्न के मायात के लिए पी॰ एक॰ 480 के मधीन संयुक्त राज्य भमेरिका की सरकार के साथ एक करार किया । इसके क्षाया, हमें कनाडा से काफी मधिक परिमाण में भन्न-सहायता भीर मास्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन के भी मन्तर्राष्ट्रीय मन्न प्रबन्ध के मन्तर्गत कुछ सहायता मिलती रही । इस प्रकार, जो मन्न-सहायता मिलना तय हो गया है उसमें से भिषकतर सहायता का भायात भगले वर्ष हो होगा। माननीय सक्त्य यह भी महसूस करेंगे कि मन्न भीर हृषि-सम्बन्धी कच्छे माल के रियायती भायात का प्रबन्ध मभी भीर कुछ समय तक भावश्यक होगा। इसलिए पी० एल॰ 480 सम्बन्धी भनुदानों को खोड़कर, जिनका जिक राजस्व-भनुमानों में किया गया है, पी० एल॰ 480 सम्बन्धी भेन-देनों भीर दूसरी भन्न-सहायता के फलस्वरूप बजट के लिए वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली सहायता भगले वर्ष के लिए 224 करोड़ स्पया भांकी गयी है अब कि वह इस वर्ष के लिए 226 करोड़ रुपया भांकी गयी है।
- 17. देश के भन्दर लिये जाने वाले ऋणों भौर विदेशी सहायता से मिलने वाली रकम के 13 करोड़ रुपये की जो वृद्धि होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पूंजी खाते के रक्षा सम्बन्धी व्यय में 17 करोड़ रुपये की भौर सीमावर्ती सड़कों सम्बन्धी व्यय म 4 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी ।
- 18. जहां तक भन्य पूंजीगत सेन-देनों का सम्बन्ध है, भ्रम भौर रासायनिक खाद दोनों के लेन-देनों से 76 करोड़ रुपये की भिषक प्राप्ति होगी। भ्रम्न निगम (फूड कारपोरे-बन) के पास मार्च 1969 के भन्त में सम्भवतः कुल 35 लाख मेट्रिक टन भ्रम्न का संग्रह हो जायगा। हम चाहते हैं कि भ्रगले वर्ष इसमें भौर 15 लाख मेट्रिक टन भ्रम्न की वृद्धि कर दी जाय। हमारा इरादा है कि इस काम के लिए 1969-70 के बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय। भ्रायदयक रकम का शेष भाग भ्रम्न निगम को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भ्रम्ण के रूप में दिया जायगा।
- 19. श्रम श्रीर रासायनिक खाद के नेन-देनों से होने वाली श्रधिक प्राप्ति राजस्व खाते श्रीर पूंजी खाते में होने वाली पूर्वोक्त क्यय-वृद्धियों से श्रीर विभिन्न विविध ऋण-जमा

शीर्षकों के मन्तर्गत होने वाली कम प्राप्तियों से समाप्त हो जायगी । मुझे राज्यों द्वारा केन्द्र को चुकायी जाने वाली रकमों में कुछ, फेर-बदल करके उन्हें कुछ, राहत पहुंचाने की और कुछ, राज्यों के प्रायोजना-क्यय से भिन्न व्यय के लिए धन की कमी दूर करने के लिए उनकी सहायता करने की भी व्यवस्था करनी पड़ी है ताकि राज्य श्रगले वर्ष संतोषप्रद ग्रायोजना का काम शुरू कर सकें। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि करों की वर्तमान दरों शौर देश के श्रन्दर लिये जाने वाले ऋणों तथा विदेशी सहायता से जितने साधन उपलब्ध हो सकेंगे उनसे केन्द्रीय सरकार के श्रगले वर्ष के बजट में ग्रायोजना के लिए और श्रिषक व्यवस्था करने की कोई गंजाइश नहीं है।

- 20. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बजट-सम्बन्धी ग्रंशदान में अगले वर्ष चालू वर्ष की तुलना में सम्भवतः कोई खास वृद्धि नहीं होगी । प्रशासनिक सुधार ग्रायोग ने ग्रीर सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरो ग्राफ पब्लिक एंण्टरप्राइजेज) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ग्रीर ग्रंचिली तरह काम करने के प्रश्न की विस्तार से छानबीन की है। सरकार इन उपक्रमों के काम को सुधारन के लिए कई फैसले कर चुकी है। मैं इस विषय पर एक जायन माननीय सदस्यों में झलग से वितरित करा रहा हूं।
- 21. माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि क्या ध्रायोजना के लिए उपलब्ध साधन, ध्रायोजना-व्यय से भिन्न घ्यय कम करके, बढ़ाये नहीं जा सकते थे। मैंने ध्रगले वर्ष के घ्यय के ध्रनुमान तैयार करते समय इस प्रश्न पर घ्यानपूर्वक विचार किया है। पर माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि ध्रायोजना-च्यय से भिन्न व्यय में कुछ वृद्धि होना तो ध्रनिवार्य है क्योंकि वह संविद्यागत दायित्व (काण्ट्रैक्चुधल ध्राब्लिगेशन) या पहले किये जा चुके फैसलों के कारण होती है। ध्रसैनिक व्यय में जो वृद्धि होनी है उसमें से ध्रधिकतर वृद्धि, पूरी की गयी ध्रायोजनागत योजनाध्रों को ध्रायोजना के क्षेत्र से ख्रलग किये जाने से, ब्याज-प्रभारों से, निर्यात-प्रोत्साहन से, मंहगाई भत्ते सम्बन्धी व्यय से, मंहगाई भत्ता वेतन में मिलाये जाने से ध्रीर वित्त ध्रायोग की सिफारिशों से होनी है। ये सब बानें संविद्यागत दायित्व या पहले किये जा चुके फैसलों की कोटि में ध्राती हैं। रक्षा-सम्बन्धी व्यय में होने वाली 59 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—वेतनों ध्रीर पेंशनों में होने वाली सामान्य वृद्धि, ध्रतिरिक्त मंहगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया, महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना, रक्षा-मन्त्रालय के ध्रधिकार में स्थित उत्पादन-एककों में लगायी जाने वाली ध्रतिरिक्त सामान्य शेयर पंजी ध्रौर पहले की गयी संविद्याशों के ध्राधार पर ग्रपेक्षाकृत ध्रधिक सामान्य की प्राप्ति।
- 22. मुझे श्रव शायद इस बात की भी कुछ चर्चा करनी चाहिए कि श्रगले वर्ष घाटे की वित्त-ध्यवस्था कितनी की जा सकती है। घाटे की वित्त-ध्यवस्था का परिमाण बजट की श्रावश्यकताश्रों के रूप में नहीं निर्धारित किया जा सकता। उसका निर्धारण उत्पादन की सम्भाव्य वृद्धि को श्रौर लोगों की बचत करने की श्रावत को देखते हुए श्रर्यव्यवस्था की श्रावश्यकताश्रों के श्राधार पर करना पड़ता है। हर बात का विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि अगले वर्ष बजट सम्बन्धी घाटा मोटे तौर पर उतना ही रखा जाये जितना इस वर्ष रखा गया तो मूल्यों को स्थिर रखने श्रौर विकास के लिए अनुकल वातावरण बनाये रखने में सम्भवतः श्रिधक से श्रीधक तालमेल बेटेगा।
- 23. इसी भूमिका के श्राधार पर मैं श्रब श्रगले वर्ष के लिए साधन एकल करने के श्रपने प्रस्ताव पेश करता हूं। ये प्रस्ताव तैयार करने में मैंने श्रायोजना-परिव्यय का कोई वांछित स्तर पहले निश्चित करने श्रौर तब श्रावश्यक साधन जुटाने का श्रासान तरीका नहीं ग्रपनाया है। कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनसे

श्रधिक साधन, श्रयंव्यवस्था का काम बिगाड़े बिना, थोड़ी श्रविध में नहीं जुटाये जा सकते । वार्षिक बजट में किसी वर्ष की श्रावश्यकताश्रों का ही नहीं बिल्क दीर्घकालीन विकास की श्रावश्यकताश्रों का भी, समान रूप से, विचार करना पड़ता है । श्रन्य शब्दों में, जो तरीका श्रपनाना श्रावश्यक है वह यह है कि सरकार में—बिल्क सामान्य श्रयंव्यवस्था में—कमशः बढ़ते हुए विकास-व्यय का बोझ बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करने के लिए करों के ढांचे में जो परिवर्तन करना श्रावश्यक श्रौर व्यवहार्य हों वे किये जायें श्रौर इस प्रकार कुल जितने साधन प्राप्त हो सकों उनकी सीमा के श्रन्दर छोटी श्रविध के लिए व्यय के प्रस्ताय किये जायें।

- 24. माननीय सदस्य भ्रब यह जानने के लिए स्वभावतः उत्सुक होंगे कि मैं श्रपनी ही कसौटियों पर कितना खरा उतरता हूं। मैं श्राणा करता हूं कि वे मेरे बारे में श्रपनी राय कायम करते हुए मेरे प्रति वही उदारता का भाव रखेंगे जो वित्त-मंत्रियों के प्रति श्रामतौर पर रखा जाता है तथा मुझे उससे केवल इस कारण बंचित नहीं करेंगे कि इस सभा में श्रपनी ही कसौटियों पर कसे जाने की यह कठिन स्थिति मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है।
 - 25. स्यूल रूप से मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों के ये उद्देश्य हैं:---
 - (क) जहां तक जरूरी समझा जाये, खासकर निर्यात, बचत श्रीर मूल उद्योग-धन्धों के श्राध्निकरण के काम में श्रोत्साहन देना;
 - (ख) ग्रसंगतियों को दूर करना;
 - (ग) कर-प्रणाली को तर्कसंगत और सरल बनाने की और व्यवस्था करना;
 - (घ) करों से बचने श्रौर श्रामदनी छिपाकर या श्रौर किसी तरह से कर न देने के रास्ते बन्द करना;
 - (ङ) जिन वस्तुश्रों या जिन स्नामदिनयों पर श्रव तक कर नहीं लगाया गया है या बहुत कम कर लगाया गया है उन वस्तुश्रों की खपत की श्रावश्यकता या उन स्नामदिनयों से कर देने की क्षमता का विचार करके उन पर कर लगाकर कर-भार को स्रिधिक समान रूप से फैलाना;
 - (च) सामान्यतः कर प्रणाली को भ्राथिक विकास के हित में भ्रधिक भ्रनुकूल बनाना

इससे पहले कि माननीय सदस्य यह सोचें कि मैं ग्रब उनके लिए भोजन परसने ही वाला हूं मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके लिए समय-समय पर क्षुधावर्धक चीजें लाता रहूंगा। मैं यहां मुख्य मुख्य चीजें ही पेश करूंगा। छोटी-छोटी चीजें व्याख्यात्मक ज्ञापन से ली जा सकती हैं।

सीमा शुल्क

26. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूपी देवी को प्रसम करने के लिए मैं उसके श्रागे नैवेद्य के रूप में निर्यात-शुक्क संबंधी रियायतें रखना चाहता हूं। मैं जूट हेसियन के निर्यात-शुक्क को 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 200 रुपया प्रति मेट्रिक टन करना चाहता हूं। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि जूट के टाट (जूट सैंकिंग) का निर्यात-शुक्क 250 रुपये प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 150 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाय तथा वूल सैंक श्रौर काटन वेंगिंग का निर्यात-शुक्क हटा दिया जाये। चाय का निर्यात-शुक्क घटा कर 20 प्रतिशत प्रति किलोग्राम से 15 प्रतिशत प्रति किलोग्राम किया जा रहा है श्रौर उस पर दी जाने वाली छूट बढ़ा कर 35 पैसे प्रति किलोग्राम से 55 पैसे प्रति किलोग्राम की

जा रही है। चरबी रिहत कच्चे ऊन पर भ्रीर धातु के डिब्बों में बन्द चाय पर लगा हुमा निर्यात-मूत्क भी हटाया जा रहा है भ्रीर दूसर प्रकार के डिब्बों में बन्द चाय का निर्यात-शुल्क 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जा रहा है। जो भ्रबरक छोटे खुले टुकड़ों के रूप में होता है उसका निर्यात-शुल्क 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जा रहा है। निर्यात-शुल्क में की जाने वाली इन किमयों से राजस्य में प्रतिवर्ष 23 करोड़ रुपये की कमी होगी।

- 27. हम शौकीनी की सभी चीजों पर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार प्रायात शुल्क लगातें हैं। विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटरगाड़ियों पर 60 प्रतिशत ग्रायात शुल्क हैं। मेरा प्रस्ताव है कि विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटरगाड़ियों के ग्रायात-शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करके हैं सियत की निशानी के रूप में उनका मूल्य बढ़ा दिया जाये। जहां तक सुखाये हुए फलों का सम्बन्ध है, श्रायात-शुल्क निर्धारित करने के लिए किया जाने वाला उनका मूल्याकन श्रवास्तविक है। मैं चाहता हूं कि उनके मूल्यांकन के लिए श्रिधक वास्तविक ग्राधार ग्रपनाथा जाय जिसके परिणाम-स्वरूप शुल्क की वसूली बड़ जायेगी। लुक्निटिंग तेलों का भ्रायात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत से 27 र्ड प्रतिशत किया जा रहा है ताकि यह मशीनों के ग्रायात-शुल्क के बराबर हो जाए, जिनमें थे तेल इस्तेमाल किये जाते हैं, ग्रीर देश में इस प्रकार के तेलों का उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिले। इन परिवर्तनों से 6.2 करोड़ ह्राये का राजस्व प्राप्त होगा।
- 28. जब किसी वस्तु पर उत्पादन-शृत्क लगाया जाता है तब हम उस पर प्रतिसन्तुलनकारी (काउन्टरवेलिंग) प्रायात-शृत्क लगाते हैं। हमें उत्पादन-शृत्क वाली किसी वस्तु में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल ग्रौर संघटक भागों पर उत्पादन-शृत्क के बवले प्रतिसन्तुलनकारी शृत्क लगाने का प्रधिकार है। पर जब वस्तु पर ही उत्पादन-शृत्क न लगा हो तब हमें ऐसा ग्रधिकार नहीं है। मैं इस द्वृद्धि को दूर करने का ग्रधिकार प्राप्त करना चाहता हं ताकि विदेशों से मंगायी जाने वाली चीजें देश में बनाने के लिए बढ़ावा मिले। बेंगरिंग, जहाजों के सामान ग्रौर व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाक या हवाई जहाज द्वारा बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों जैसे कुछ मामलों में, उपयोग के प्रनुसार दरें या वर्गीकरण बहुत ज्यादा होने के कारण, बेंगतलब की देर ग्रौर परेशानी होती है। मैं इस कठिनाई को भी दूर करना चाहता हूं।

उत्पादन शुल्क

- 29. उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में प्रव सामान्यतः यह माना जाता है कि मूल्यानुसार शुल्क परिमाण-शुल्कों से ग्रधिक युक्तिसंगत हैं क्योंकि परिमाण-शुल्कों का भार, जब मूल्य बढ़ते हैं तब घटता है ग्रीर जब मूल्य घटते हैं तब बढ़तः है। मुल्यानुसार शुल्क लागत ग्रीर कीमत घटाने के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सीमेन्ट, बनास्पति, बिजली के पंछों, बिजली के लट्टुओं ग्रीर ट्यूगें, साबुन, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा ग्रीर सोडियम सिलिकेट पर लगे हुए वर्तमान परिमाण-शुल्कों को मूल्यानुसार शुल्कों में बदल दिया जाए। पुर्णांकन (राउंडिंग) की भ्रावश्यकता के बावजूद मैंने ऐसा करके राजकोष के लिए काफी रकमें प्राप्त करने के लोभ का संबरण किया है।
- 30. पर प्रत्येक नियम का अपवाद होता है। इस नियम को सिद्ध करने के लिए अपवाद निश्चित करने में एक विशेष परिस्थित से मुझे सहायता मिली है। इस समय, नियन्त्रित मूल्य पर ही जाने वाली चीनी की एक कीमत है और खुले वाजार में मिलने वाली चीनी की और कीमत है। यह स्पष्ट है कि जब चीनी के वर्तमान परिमाण-शुल्क को मूल्यानसार शुल्क में बदल दिया जायेगा तब गुल्क की दो दरें हो जायेंगी। इन दो दरों में से एक दर चुनने में मैंने नियन्त्रित मूल्य पर दी जाने वाली

षीनी की कुछ तरफवारी की है जिस पर लगे हुए वर्तमान बुनियादी भीर प्रतिरिक्त मुल्कों की मूल्यानुसार वर भीसतन लगभग 23 प्रतिशत निकलती है। मैंने यह वर सभी धानेदार जीनी पर लगायी है। इस प्रकार, नियन्तित जीनी की भीसत कीमत में कोई फेरबदल नहीं होगा भीर विभिन्न कोलों में उसकी कीमत में बहुत थोड़े परिवर्तन होंगे। इसी प्रकार, खांडसारी पर 12.5 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर लगायी जा रही है और वर्तमान संयुक्त (कंपांडडिंग) दरों में उपयुक्त फेरबदल किया जा रहा है। मैं भाशा करता हूं कि जिस मूल्यानुसार दर से नियन्तित चीनी पर शुल्क लगाने का विचार है उसी दर से खुले बाजार में मिलने वाली चीनी पर शुल्क लगाये जाने पर माननीय सदस्य सिर्फ इस कारण आपत्ति नहीं करेंगे कि इससे प्रसंगवश 27 45 करोड़ रुपये का भतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

- 31. मेरा प्रस्ताव है कि घरों में इस्तेमाल किये जाने वाले बिजली के उल्लिखित उपकरणों भर और परिरक्षित (प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों पर 10 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से उत्पादन, शुल्क लगाया जाय। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष काउन काकों पर (बोतलों ब्रादि का मुंह बन्द करने के कागों पर) 1 पैसा प्रति कार्क शुल्क लगाया गया था। बच भेरा यह प्रस्ताव है कि बहु शुल्क बोतलों धीर पानों का मुह बन्द करने के ब्रन्थ प्रकार के ढकनों पर भी लगा दिया जाय। बिजली के उपकरणों, परिरक्षित खाद्य पदार्थों और चौर्य रक्षित (पिल्फर प्रूफ) ढ़कनों पर लगाये जाने वाले इन उत्पादन-शुल्कों से 4 करोड़ रुपये का राजस्य प्राप्त होगा।
- 32. माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों को कृषि तथा अनुसन्धान, सिंचाई की सुविधाओं और रासायनिक खाद के कारखानों में किये गये हमारे बड़े बड़े निवेशों, गांवों में लगायी गयी बिजली, ऋण-सुविधाओं और मूल्यों की गिरने से रोकने की हमारी नीति से लाभ होता है उन्हें अपने लाभ का कुछ हिस्सा आम विकास के खर्च के लिए दे देना चाहिये। यह इस कारण और भी अधिक आवश्यक है कि अभी हमारे अधिकतर किसानों को, खासकर सूखे प्रदेशों में, जहां रासायनिक खाद और नये बीज इस्तेमाल करना आसान नहों है, समुन्तत उद्योग तो विद्या (टेक्नालाजी) का लाभ नहों मिल सकता। इसी प्रकार, शक्ति-चालित पम्पों से पानी को ऊपर चढ़ा कर सिचाई करने की सुविधाओं का विस्तार सर्वत समान रूप से नहीं हुआ है। यदि नयी कृषि उद्योग-विद्या का लाभ कमशः इमारे अधिकाधिक किसानों को पहुंचाना है, तो इस काम के लिए आवश्यक साधन इस काम से लाभ उठाने वालों से, कम से कम अंशतः, प्राप्त होने चाहियें। इस आधार पर मेरा यह प्रस्ताव है कि रासायनिक खादों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार पादन-शुल्क और शक्ति-चालित पंपों पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन-शुल्क लगाया जाय। इन शुल्कों से 24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से 22 करोड रुपया रासायनिक खाद के शुल्कों से मिलेगा।
- 33. प्रब मुझे फिर क्षुधावर्धक वस्तुएं पेग करनी चाहियें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिये यह कठिनाई का समय है। इसिलये उत्पादन-शुल्क में कुछ राहत देना जरूरी है। सादी सीधी रीलों की लच्छियों के रूप में होने वाले सूत पर लगा हुम्रा उत्पादन-शुल्क कुछ सूत्रांकों (काउण्ट) के सम्बन्ध में हटा दिया जा रहा है भौर कुछ अन्य सूत्रांकों के सम्बन्ध में घटाया जा रहा है। इस से हथकरघा क्षेत्र को लाभ होना चाहिये। बिजली के करघे के क्षेत्र को, कलफ लगाने पर लगा हुम्रा भिन्नक शुल्क (डिफरेंशल इयूटी) हटा दिये जाने से लाभ होगा, यद्यपि कुछ सूत्रांकों के, बिना कलफ के बारीक (फाइन) श्रोर बहुत बारीक (सुपरफाइन) सूत का उत्पादन-शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि घूसर (ग्रे) कपड़े पर लगा हुग्रा उत्पादन-शुल्क हटा दिया जाए श्रौर परिष्करण (प्रोसेसिंग) सम्बन्धी श्रिधभार मीडियम ए ग्रौर श्रानयंत्रित मीडियम बी की सभी किस्मों के कपड़े श्रौर मोटी किस्मों के कपड़े पर प्रति वर्ग मीटर पांच पैसे घटा दिया जाय। इस राहत से सूती कपड़े की कमजोर मिलों को बहुत लाभ होगा। कुल प्रस्तावित राहत की रकम 15 30 करोड़ रुपया होगी।

- 34. पर इस हानि में से 9:5 करोड़ रुपये की पूर्ति नियंत्रित किस्मों के छपे कपड़े को छोड़ बहुत बारीक तथ: बारीक किस्म के छपे कपड़े पर 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर श्रीर दूसरी सब किस्मों के छपे कपड़े पर 2:5 पैसे प्रति वर्ग मीटर का श्रीर ऊंचा शुल्क लगाकर तथा ज्यादा कीमती किस्मों के कपड़ों, जैसे 'सूट', के कपड़ों, परदे श्रीर सजाबट के कपड़ों, टिकिश तौलियों श्रीर दूसरे कपड़ों पर जिन पर इस समय उनको कीमत को देखते हुए शुल्क का भार कम है, छंटाई के श्राधार पर 15 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगाकर, की जायगी। इसके अलावा, बिजली के करघों के कपड़ों पर लगे हुए वर्नमान संयुक्त (कम्पा-उण्डेड) शुल्क को दुगना करने श्रीर कपड़े के टुकड़ों (फेंट) पर लग हुए शुल्कों को युक्ति-संगत करने का भी मेरा विवार है।
- 35. नीचे के 'डेनियरों' क नाइलन के धारी पर लगा हुआ उत्पादन-मुल्क घटाया जा रहा है और इससे होने वाली हानि की कुछ पूर्ति कतिपय ऊंचे 'डेनियरों' के नाइलन के धारी पर लगा हुआ उत्पादन-मुल्क कुछ बढ़ाकर की जायगी। इस घट-बढ़ का परिणाम यह होगा कि राजस्व 3'9 करोड़ रुपया कम हो जायगा। इस रियायत से नाइलन के धारों का चोरी से देश में लाया जाना बंद करने में सहायता मिलेगी। नाइलन के धारों का चोरी से लाया जाना बंदी चिंता का विषय हो गया है।
- 36. 'कनफेक्शनरी' पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क घटाकर 80 पैसे प्रति किलोग्राम से 30 पैसे प्रति किलोग्राम किया जा रहा है, पर चाकलेटों पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क नहीं घटाया जा रहा है। रेडियो-निर्माताओं द्वारा संघटकों के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले इलैक्ट्रानिक वाल्यों, ट्रान्जिस्टरों और सेमी कण्डक्टर डायोडों पर लगा हुआ शुल्क घटाकर आधा कर दिया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के बड़े-बड़े निर्माताओं द्वारा बनाये जाने वाले कम कीमत वाले रेडियो-सेटों पर 10 रुपया प्रति सेट शुल्क लगेगा। बिजली की भट्टियों के मालिकों द्वारा रही लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों और अन्य चीजों के सम्बन्ध में, डलों पर लगे हुए उत्पादन-शुल्क की सीमा तक, छूट देने का मेरा विचार है। कसीदे पर लगाया गया उत्पादन-शुल्क घटाया जा रहा है क्योंकि उसका भार बहुत अधिक साबित हो रहा है। मैं अच्छे आधार पर इस विषय में आण्यस्त हूं कि सिनेमा की अस्त-व्यस्त दुनियां में अधिकतम निपुणता उन लोगों को प्राप्त है जो काले और सफेद का विचार करने के अध्यस्त हैं। इसलिये काली और सफेद का विचार करने के अध्यस्त हैं। इसलिये काली और सफेद किनमा फिल्मों को कुछ राहत देना चाहता हूं और रंगीन फिल्मों का शुल्क-भार बढ़ाना चाहता हूं। कच्ची सिनेमा फिल्मों पर भी दो पैसे प्रति मीटर का नाममात्र शुल्क लगाना चाहता हूं। कनफेवणनरी, रेडियो क संघटक भागों, रही लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों, कसीदे और सिनेमा फिल्मों के सम्बन्ध में दी गई कई प्रकार की रियायतों का परिणाम कुल मिला कर यह होगा कि राजस्व 3: 13 करोड़ रुपया कम हो जायगा।
- 37. श्रव फिर श्राधिक परिचित चीजों की चर्चा करता हूं। मैं समझता हूं कि वह समय श्रा गया है जब सर्वेद्ध श्रौर बहुत समय से अप्रत्यक्ष कर का बोझ ईमानदारी से उठाने वाली चीजों में से कुछ की, जैसे सिगरेटों झौर मोटर स्प्रिटों को उन पर प्रति वर्ष लादे जाने वाले वोझ से मुक्त किया जाना चाहिये। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि शुल्क यथेष्ट रूप से बढ़ाये जायें। मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि मैंने अपने पिछले दो बजटों में इस सम्बन्ध में यथेष्ट कार्रवाई नहीं की। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि मोटर स्प्रिट पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 7 पैसे प्रति लिटर बढ़ा दिया जाय और सिगरेटों पर लगे हुँ उद्यादन-शुल्क में, विभिन्न मूल्य खण्डों में, मूल्यानुसार 6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाय। इससे 29 84 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। बढ़िया किस्म का मिट्टी का तेल, मोटर के इँधन-तेल में अधिकाधिक मिलाया जा रहा है। इस लिये उस का उत्पादन शुल्क भी 4 पैसा प्रति लिटर बढ़ाया जा रहा है। इससे 14 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

- 38. जट की बती चीजों पर लगा हुआ श्विमादी उत्पादन-शुल्क 100 हाया प्रति मेट्रिक टन बढ़ाया जा रह है। इस शृ से 4'95 करोड़ हपए का राजस्व प्राः होगा। सेल्यूलोजी रेशे (स्टेपुल फाइबर) पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 20 पैसा प्रति किलोग्राम और गैर-सेल्यूलोजी रेशे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 12 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ाया जा रहा है। रेयन के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क औद्योगिक डेनियरों को छोड़ अन्य सभी डेनियरों में वर्तमान दरों का लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और रेयन के धागे के बड़े उत्पादकों की तुलना में छोटे उत्पादकों को शुल्क की दरों में जो रियायत मिलती है वह भी घटायी जा रही है। कृत्निम रेशों और थारों के संबंध में किये गये इन प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 9'37 करोड़ रुपये का प्रतिरिक्त राजस्य प्राप्त होगा। उन्न के धागे के शल्क को वहां से हटाकर उन की पूनियों पर लगा देने का भी मेरा इरादा है; आरम्भ में मैं उन की पूनियों पर थोड़ा-सा श्रांत्क लगा रहा हूं जिससे 6 लाख रुपया प्राप्त होगा।
- 39. उत्पादन-शुल्कों के संबंध में किये गये सब प्रस्तायों और कुछ छोटी-मोटी विविध बातों का सम्मिलित परिणाम यह होगा कि पूरे वर्ष में 104'57 करोड़ रुपए का प्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें स 79'95 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा थ्रौर 24'62 करोड़ रुपया राज्यों का हिस्सा होगा। उत्पादन-शुल्कों के संबंध में किये गये प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्क से, मुख्यतः रासायनिक खाद के श्रायात पर लगे हुए प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से 26 करोड़ रुपये की श्रतिरिक्त प्राप्ति होगी।
- 40. निर्धारिती द्वारा उत्पादन-शुल्क की रकम स्वयं हिसाब लगा कर निकाले जाने और माल हटाये जाने की जो योजना जून 1968 से जारी की गयी है वह अच्छी तरह अमल में आयी है और मैं उसे यथासंमव शीघ्र से शीघ्र उत्पादन-शुल्क वाली अधिकतर वस्तुश्रों पर लागू करना चाहता हूं।

प्रत्यक्ष कराधान

- 41. निगम कराधान के सम्बन्ध में भेरा प्रस्ताव है कि नये ग्रीद्योगिक उपक्रमों ग्रीर जहाजों को दी गई कर-अवकाण सम्बन्धी रियायत (टेक्स हालिडें कंसेशन) की ग्रवधि, 1 ग्रप्रैल 1971 से 31 मार्च 1976 तक की पच वर्षों की ग्रवधि के लिये बढ़ा दी जाय। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि विकास छूट सम्बन्धी सुपरिचित साधन को समाप्त करने या उसके स्थान पर कोई दूसरा नया साधन ग्रपनाने की जरूरत नहीं है। इसलिये विकास छूट सम्बन्धी रियायत दिया जाना जारी रहेगा, पर 31 मार्च 1970 से बाद लगायी जाने वाली मणीनों ग्रीर संयंत्रों के सम्बन्ध में विकास छूट, कानून में पहले से निर्धारित की गयी कम दरों पर दी जायगी। बहुजनधारित देशी कम्पनी द्वारा ग्रथ्यत्—जिस देशी कम्पनी के ग्रेयर श्रधिक लोगों के पास हों उसके द्वारा देय कुल निगमकर की ग्रधिकतम सीमा, जो कम्पनी (लाभ) ग्रतिकर ग्रधिनियम में उस क पनी की कुल ग्राय का 70 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, ग्रब ग्रथिति हो गयी है। पर लोगों को उससे गलतफहमी हाती है जैसे यह ग्रथमां सीमा भी काई प्रचिति दर हो। इालिए में जह स्ताव है कि यह सीमा ग्रब समाप्त कर दी जाय। अब वे पत्लिक कम्पनियां जिनके शेयर मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों की सूचियों में दर्ज हों, बहुजनधारित कन्पनियां मानी जायंगी।
- 42. विदेशों से तही उद्योग-विद्या बार-बार प्राप्त करने में ज्यादा से ज्यादा कमी करने ग्रीर वस्तत: देश में तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि उन भार-तीय कम्पनियों की ग्राय पर, जो ऐसे ज्ञान को बेचकर या उसके द्वारा सेवा करके कमाई करती है, रिया ती श्राधार पर कर लगाया जाय। हमारे देश के दो महत्वपूर्ण निर्यात-सहायक

उद्योगों भ्रयात्—सूती श्रौर जट वस्त्र उद्योगों को भ्राधुनिक बनाने में प्रोत्साहन देने के लिये मैं इन दोनों उद्योगों को विकास छूट देने के उद्देश्य से प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

- 43. श्रायकर प्रधिनियम तथा उससे सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने के लिये एक बिस्तृत विधेयक संसद के इस श्रधिवेशन में, बाद में, पेश करने का मेरा विचार है। इस विधेयक में मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि जिन भारतीय कम्पनियों को इस समझ मूल्यहास सम्बन्धी छूटें तथा श्रन्य छूटें पाने का श्रधिकार नहीं है उनके द्वारा प्रोत्साहन, प्रायोजना रिपोर्ट, मंडियों की खोज श्रावि के लिये किया गया व्यय, 10 वर्ष की श्रविध में, उनकी कर-योग्य श्रामदनी में से घटा दिया जाय। इस प्रकार घटायी जाने वाली रक्ष प्रायोजना की लागत के 2½ प्रतिशत भाग तक सीमित होगी। मूल्यहास के लिये विभिन्न प्रकार की मशीनों के वर्गीकरण करने का तरीका काफी सरल बनाया जा रहा है श्रीर मशीनों बथा संयंत्रों के मूल्यहास के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट की सामान्य दर बढ़ाकर 7 प्रति— वत से 10 प्रतिशत की जा रही है।
- 44. व्यक्तिगत धायकर की दरों में क्रिमक वृद्धि करने के उद्देश्य से 10,001 रुपवे के 15,000 रुपये तक की धामदिनियों के कर की दर में 2 प्रतिशत की धोड़ी वृद्धि करके धर्थात् उसे 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 17 प्रतिशत करने धर्मीर 15,001 रुपये से 20,000 रुपये तक की धामदिनियों के कर की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने धर्यात् उसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है, इन वृद्धियों का पूरा प्रभाव उन कर-दाताओं पर पड़ेबा जिनकी आय प्रतिवर्ष 20,000 रुपया या उससे अधिक होगी। बुनियादी आयकर के 16 प्रतिशत के अधिभार (सरवार्ज) को मिलाने पर इस प्रकार के प्रत्येक मामले में धितिरुक्त कर की रकम 275 रुपया प्रतिवर्ष होगी। आयकर की दरों में किये गये इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 13 82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्य प्राप्त होगा।
- 45. सहकारी सिमितियों पर लगाय जाने वाले करों को सरल ग्रौर युवितसंगत बनाने का मेरा प्रस्ताव है। रिजस्टर्ड फर्मों के सम्बन्ध में 10,001 रुपये से 25,000 रुपए तक की भामदिनयों का एक ग्रौर खण्ड बना कर ऐसी फर्मों पर किये जाने वाले कराधान में योड़ी सी वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। उपर्युक्त ग्रायखण्ड की फर्मों पर लगने वाले बुनियादी ग्रायकर की दर 4 प्रतिशत होगी। इस परिवर्तन से पूरे वर्ष में 4:32 करोड़ रुपये का ग्रातिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
- 46. लेखकों, कलाकारों, नाट्यकारों, गायकों श्रीर श्रिभनेताश्रों को मैं विशेष प्रसन्नका का समाचार देना चाहता हूं। उनकी व्यावसायिक श्राय का, जो उन्हें विदेशी स्रोतों से विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त होगी, 25 प्रतिशत भाग कर-योग्य श्राय में से घटा दिया जायगा। यदि मेरे इस प्रस्ताव से माननीय सदस्य यह समझें कि इसके कारण हमारी सांस्कृतिक क्षति होगी तो मैं माननीय सदस्यों का क्यान इस तथ्य की श्रोर दिलाना चाहूंगा कि सर्वोत्तम वस्तुएं निर्यात के लिए होनी हैं।
- 47. माननीय सदस्य जानते ही हैं कि वास्तविक निवेशकों में सामान्य शेयरों में धन लगाने की रुचि फिर से पैदा हुई है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कम्पनियों से लाभांश के रूप में होने वाली श्राय के लिए कर से छूट देने की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति वर्ष करने का मेरा प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से भारतीय कम्पनियों के शेयरों में लागयी जाने वाली पूंजी यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में लगायी जाने वाली पूंजी के बराबर हो जायगी। जीवन बीमा की किस्तों के सम्बन्ध में इस समय कर में दी जाने वाली राहत का क्षेत्र बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

- 48. कृषि-सम्बन्धी सम्पत्ति पर ग्रभी तक सम्पत्ति कर नहीं लगता । इसर्से सुविधा से ग्रधिक धनी व्यावसायिक तथा व्यापारिक वर्गों को जमीन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिला है। माना कि इसते कभी कभी कृषि ी उत्पादकता बढाने के लिए प्रोत्साहन मिलता ह परन्तु सामान्य अर्थ-व्यवस्था में यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि ग्रन्य उत्पादनकारी सम्पत्ति पर तो कर लगाया जाय पर कृषि भूमि सञ्बन्धी सम्पत्ति को कर से छुट दी जाय । महान्यायबादी ने मुझे परामर्ण दिया है कि संसद को कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर लगाने के लिए कानून बनाने का श्रधिकार है। तदानुसार सम्वत्ति कर ग्रधियिनम में कृषि-भमि के मत्य पर, जिसमें उस भूमि पर या उसके पास स्थित इमारतों का मुख्य शामिल है, सम्पत्ति कर लगाने की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है । लेकिन खड़ी फसलों, श्रौजारों, श्रौर ट्रैक्टर जैमे उपकरणों पर कोई कर नहीं लगाया जायगा निर्धारण वर्ष 1970-71 से प्रचलित दरों पर कर-निर्धारण के लिए कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति दूसरी सम्पत्ति में जोड़ की जायगी । इस तरीके से पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपये के श्रतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी । लेकिन, मैंने श्रभी जो कहा है, उसके कारण, ग्रागामी वर्ष में राजस्व सम्बन्धी कोई लाभ नहीं होगा । कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर लगाये जाने से होने वाली वास्तविक राजस्व-प्राप्तियां राज्यों को सहायक श्रनुदानों के रूप में दे देने का मेरा विचार है । फिर भी इस उपाय के प्रभाव से वास्तविक िकसानों को मुक्त रखने के तरीके पर मैं विचार करूंगा श्रौर वित्त विधेयक में उपयुक्त समय पर श्रावश्यक संगोधन का प्रस्ताव करूंगा।
- 49. श्रियम कर श्रदायगी योजना को श्रिधक प्रभावकारी श्रीर छोटे छोटे ग्रायकर-दाताश्रों पर श्रदायगी का भार कम करने के लिए भी मैं उक्त योजना में कई परिवर्नन करने के प्रस्ताव कर रहा हूं। सम्पत्ति कर श्रिधिनयम के श्रधीन वास्तविक सम्पत्ति का विवरण न देने श्रीर हिसाब-किताब, कागजात श्रादि पेश न करने के लिए किये जाने वाले जुर्मानों में कुछ परिवर्नन करने का भी मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। एक श्रीर प्रस्तावित परिवर्नन का उद्देश्य कारवार के खर्च के लिए श्रदायगियां करने में कैंकों का श्रिधक इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की गयी व्यवस्था को ठीक ठीक चलाने का पक्का प्रबन्ध करना है।
- 50. माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति श्रपनी सम्पत्तिं को अपनी पत्नी/पित तथा छोट बच्चों के नाम श्रन्तरित करके श्रपनी श्राय पर कर लगाये जाने से बच नहीं सकता। फिर भी, श्रलग एकक के रूप में हिन्दू श्रिवभक्त परिवार पर कर लगाने के लिए बनाये गये विशेष कानूनों का इस्तेमाल कर के श्रक्सर इससे बचा जा सकता है। संशोधन विधेयक में उपयुक्त उपबन्ध करके कर न देने के इस रास्ते को बन्द करने का मेरा विचार है।
- 51. मैंने प्रत्यक्ष कराधान में जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है उनसे श्रगले वर्ष कुल मिलाकर केन्द्र को 11 करोड़ रुपये और राज्यों को 2.5 करोड़ रुपये का ग्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो गा

डाक और तार

52. डाक श्रीर तार विभाग को ग्रगले वर्ष भी घाटा होगा। इसलिए स्यूल रूप से ग्रुल्क हर जांच समिति की सिफारिशों के श्राधार पर टेलीफोनों ग्रीर तारों की कुछ शुल्क दरों में श्रीधसूचित की जाने वाली तारीखों से संशोधन करने का विचार है। बजट पत्नों के साथ एक कापन भी परिचालित किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्योरा दिया गया है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ग्रीर बिल्ली के चार बड़े शहरों में तथा दूसरे टेलोफोन केन्द्रों के लिए टेलोफोन का किराया बढ़ाया जायगा। बाइरेक्टरी पूछताछ सेवा पर, जो ग्रब तक नि:शुल्क थी, श्रब शुल्क लगाया जायगा। विशेष व्यक्ति (पी० पी०)ट्रेक कालों ग्रीर निर्धारित समय के ट्रंक कालों के लिए ग्रितिरिक्त शुल्क श्रव समान रूप से

बुनियादी मुल्क का 50 प्रतिमत होगा। बधाई के तारों, बहु-पता तारों भ्रौर टैलेक्स तथा कुछ भ्रौर सेवाभ्रों के मुल्क में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 6' 46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है भ्रौर यह रकम प्रत्यामित राजस्व घाटे की रकम को पूरा करने के लिए काफी होगी। इन परिवर्तनों के प्रभाव को सरकारी उपक्रमों के कुल भ्रान्तरिक साधनों का भ्रनुमान लगाने के लिए हिसाब में लिया गया है।

क्षारांश

- 53. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मैंने करों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये हैं। उनसे श्रगले वर्ष केन्द्र को लग भग 100 करोड़ रुपये का वास्तविक ग्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से 11 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से, 80 करोड़ रुपया उत्पादन-शुल्कों से ग्रौर निर्यात-शुल्कों में होने वाली 23 करोड़ रुपए की कमी को हिसाब में लेने के बाद, 9 करोड़ रुपया सीमा-शुल्कों से मिलेगा। इसके ग्रलावा, 27 करोड़ रुपया राज्यों को प्राप्त होगा।
- 54. श्रव मैं संक्षेप में साधनों के सम्बन्ध में केन्द्र की श्रगले वर्ष की स्थिति बताना चहाता कर-सम्बन्धी श्रतिरिक्त प्रस्तावों को हिसाब में लेने के बाद कुल राजस्व श्रनुमानतः 3,519 करोड रुपया होगा जिस में से 519 करोड रुपया राज्यों को श्रीर 3,000 करोड रुपया केन्द्र को मिलेगा। राजस्व खाते का ग्रायोजना-व्यय से भिन्न व्यय, जिस में राज्यों को दिये जाने वाले भ्रनुदान, ब्याज-प्रभार, भ्रौर रक्षा-सम्बन्धी व्यय शामिल है, 2,558 करोड़ रुपया श्रांका गया है । इस प्रकार भ्रायोजना से भिन्न राजस्व-श्रधिशेष 442 करोड़ रुपया रहेगा । श्रनुमान है कि चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम घटाने के बाद, बाजार-ऋणों श्रौर विदेशी ऋणों से ग्रगले वर्ष क्रमणः 106 करोड रुपए भ्रौर 691 करोड रुपए की रकम प्राप्त होगी। विविध ऋण जमा शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों को हिसाब में लेने के बाद और आयोजना से भिन्न पुंजीगत व्यय और ऋणों के लिए ---जिनमें संकट के समय काम श्राने वाले श्रन्न भण्डार के लिये निर्धारित की जाने वाली रकम श्रीर सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की नकदी हानियां शामिल हैं --व्यवस्था करने के बाद, पूंजी खाते में 1,046 करोड़ रुपया उपलब्ध होगा। इस प्रकार, केन्द्र के बजट में श्रायोजना के लिए 1,738 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध होंगे जिनमें घाटे की वित्त व्यवस्था का 250 करोड़ रुपया शामिल है। इसके भ्रलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिनमें रेलें ग्रीर डाक-तार शामिल हैं, ग्रपने साधनों में से ग्रायोजना के लिए ग्रनुमानतः 165 करोड़ रुपया जुटायेंगे। इस प्रकार, राज्यों के साधनों को छोड़ देने पर, भ्रगले वर्ष श्रायोजना के लिए कूल 1903 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध होगी। इसमें से 615 करोड़ रुपया राज्यों को दी जाने वाली श्रायोजना-सहायता के लिए श्रौर 65 करोड रुपया संघीय राज्य-क्षेत्रों को दी जाने वाली भायोजना-सहायता के लिए रखा गया है। जइस प्रकार, केन्द्रीय श्रायोजना के लिए, जिसमें केन्द्र प्रवर्तित (सेण्ट्ली स्पानसर्ड) योजनाएं शामिल हैं. 1223 करोड रुपया रहेगा।
- 55. श्रगले वर्ष के बजट में ग्रायोजना के लिए कुल 1738 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिस में से 402 करोड़ रुपया राजस्व-बजट में श्रौर 1336 करोड़ रुपया पूंजी बजट में हैं। राजस्व-खाते में की गयी व्यवस्था में राज्यों की श्रायोजनागत योजनाश्रों के लिए दिय जाने वाले सहायक श्रनुदानों के रूप में 185 करोड़ रुपये की रक्षम हैं। यह रक्षम श्रगले वर्ष से दी जाने वाली कुल श्रायोजना सहायता का 30 प्रतिशत भाग है जबिक इस समय दिये जाने वाले इन ग्रनुदानों की रक्षम श्रौसतन कुल श्रायोजना सहायता के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होती है। राजस्व-बजट में श्रायं जना के लिए की गयी व्यवस्था का शेष भाग संघीय राज्य क्षेत्रों की श्रायोजना श्रौर केन्द्रीय श्रायोजना के लिए है। केन्द्र-प्रवितित योजनाश्रों के लिए राजस्व खाते श्रौर पूंजी खाते दोनों में कुल मिलाकर 117 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

56. श्रगले वर्ष की केन्द्रीय श्रायोजना में इस्पात के उत्पदन, बन्दरगाहों, पेट्रो-रासायनिक पदार्थों के लिए, रासायनिक खाद के कारखानों, लोहे के निर्यात के लिए, खानों के विकास श्रौर सांबे तथा एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए चालू वर्ष में की गयी व्यवस्था के मुकाबले श्रधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। मुख्य रूप से परिव्यय में वृद्धि होना इस बात का सूचक है कि चालू योजनाश्रों का काम श्रधिक तेजी से किया जा रहा है। तब भी इससे निर्माण-कार्य में लगे उद्योगों, खासकर इंजीनियरी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। श्रश्न रखने के लिये भण्डार बनाने का कार्यक्रम भी तेजी से चलाने का विचार है। किसानों को ऋण देने, खासकर रासायनिक खाद के वितरण श्रौर गांवों में बिजली लगाने के संस्थागत प्रबन्ध को, बजट में उस के लिए श्राव यक सहायता की व्यवस्था करके, सुदृढ़ किया जा रहा है। परिवार-नियोजन के लिए पहले से श्रधिक परिव्यय किया जायगा।

57. महोदय, मैं इस बात पर चाहे जितना जोर दुं वह कम ही होगा कि मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर ग्रौर अगले वर्ष किये जाने वाले श्रायोजना -सम्बन्धी परिव्यय में की जाने वाली कुछ वृद्धि पर इस पुष्ठभूमि से विचार किया जाना चाहिये कि हमारे साधनों पर बहुत अधिक बोझ है । पिछले कुछ वर्षों से राजस्व खाते के श्रधिशेष में कमी होती रही है । श्रगले वर्ष केन्द्र के बजट में, करों की वर्तमान दरों के श्रनसार, राजस्व 60 करोड रुपये की कमी ग्रांकी गयी है। श्रतिरिक्त प्रस्तावित कर लगाये जाने पर भी, यह कमी केवल 40 करोड रुपये के श्रधिशेष में परिवर्तित होगी। पुंजी खाते में स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई केवल इस कारण नहीं दिखाई देती कि इस वर्ष होने वाला कुछ श्रायात श्रगले वर्ष होने से अन्न-सहायता का स्तर ऊंचा बनाये रखा गया है। ज्यों ज्यों श्रन्न के सम्बन्ध में स्नात्मिनर्भरता प्राप्त होगी त्यों त्यों यह साधन क्रमश: घटता जायगा और यदि विकास सम्बन्धी परिव्यय श्रनुचित रूप से कम नहीं किया जाना है, तो साधन जुटाने के श्रन्य उपाय निकालने पड़ेंगे। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि सामाजिक भौर राजनीतिक स्थिरता बनाये रखते हुए भौर स्वावलम्बन बढ़ाते हुए विकास का व्यापक लक्ष्य केवल बजट सम्बन्धी नीति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग श्रौर देश के प्रत्येक क्षेत्र का सूच्यवस्थित सहयोग श्रावश्यक है। केवल इस प्रकार हम इस महान राष्ट्र को जनसाधारण की गरीबी को मिटा देने के उस प्रयत्न के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं जो उतना ही फलदायक है जितना कठिन है। मैं इतनी ही आशा कर सकता हुं कि जो बजट पेश करने का सम्मान मुझे प्राप्त हम्रा है वह इस लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ सहायता प्रदान करेगा।

धन्यवाद ।

Budget 1969-70

Speech of Deputy Prime Minister and Minister of Finance 28th February, 1969

Sir,

I rise to present the first Budget of the Fourth Plan period. In doing so, I feel somewhat handicapped as the Plan document is not yet available to Honourable Members. I am, therefore, left to perform the traditional role of a Sutradhar

who must make a brief appearance on the stage before the start of the play to arouse the interest of the audience. I hope I will not disappoint Honourable Members at least on the score of brevity.

Introduction

- 2. The year that is now drawing to a close has been a good one for the Indian economy. The expectation in my last Budget speech that, given the right policies, 1968-69 could become a year of revival has been largely fulfilled. For the second year in succession, it should be possible to reap a satisfactory harvest. There are distinct signs of an industrial revival and industrial production should register an increase of almost 6 per cent. Transport activity and trade have revived; and there have been no serious shortages of powder or raw materials. The general price level now is somewhat lower than last year. There has been a remarkable increase in exports. Imports are now being replaced by domestic production over a wide front as a result of the efforts made over successive Plan periods. Despite heavier repayment obligations and somewhat lower utilization of foreign aid than in 1967-68, it should be possible to close the current year without any material variation in our foreign exchange reserves. Against this background of a new dynamism in agriculture, industrial revival, restoration of price stability and progress towards self-reliance, it is possible now to approach the next Plan period with a measure of confidence. All the same, there are a number of factors which limit considerably the area of choice before us in the immediate future.
- 3. While food production has increased, we have still a long way to go before we can assure satisfactory levels of consumption for our growing population. Imports of agricultural raw materials and foodgrains are still sizeable. Investments in agriculture, including those in research, inputs such as fertilizers and water and provision of credit and storage facilities must, therefore, have a prior claim on our limited resources matched only by the attention to family planning.
- 4. The substantial development of capital goods industries that has already taken place makes it necessary as well as feasible to step up investment outlays. But rising levels of investment can be achieved without inflation only on the basis of a growing volume of production of essential consumer goods. This requires not only a steady improvement in agricultural productivity but also greater efficiency and expansion of capacity in consumer goods industries. Attention to these industries is all the more important as they help stimulate the motivation for higher productivity and contribute to growth of public revenues.
- 5. In a year that is dedicated to the memory of the Father of the Nation, we cannot but remind ourselves that the ultimate objective of economic development is to serve certain larger social values. We have, therefore, to respond also to the natural urge of our people for basic amenities, such as drinking water, for education and medical aid, for opportunity to work and indeed for a growing measure of equality in general which is the essence of a socialist society.
- 6. On the external front, the improvement has been as notable as it is welcome; yet export earnings amount only to two-thirds of our current import requirements. There cannot, therefore, be any complacency in regard to export promotion or import substitution. The abnormal circumstances of 1965-66 and 1966-67 have led to a decline in the rate of saving in the economy. Despite substantial efforts to mobilize resources and considerable restraint on expenditure, the financial position of the Government has weakened over the past few years.
- 7. In short, general economic conditions in the country are propitious for resuming the threads of progress over a wide front during the next Plan period. Equally, however, there is need for the right balance between consumption and investment, resources and outlays, economic growth on the one hand and external viability on the other and indeed between larger social values and purely economic considerations. Honourable Members will now appreciate why economic planners are often regarded as some of the finest exponents of the art of tight-rope dancing.

Revised Estimates-1968-69.

8. Having outlined briefly the current economic situation and the tasks ahead without, I hope, stealing the show from the Planning Commission, I must now turn to the more mundane matters which fall to the lot of Finance Ministers. In the Revised Estimates for 1968-69, customs revenue will show a shortfall of Rs. 94 crores as compared to the Estimates presented last February. Union excise duties and income-tax, on the other hand, are expected to yield Rs. 54 crores more. After making allowance for non-tax revenues, total revenue receipts

accruing to the Centre are likely to show a shortfall of Rs. 11 crores only as compared to the anticipated realisation of Rs. 2760 crores.

- 9. Revenue expenditures are likely to exceed the Budget Estimates of Rs. 2629 crores by Rs. 116 crores. Almost half of this increase, however, represents a purely accounting change which is balanced by a corresponding gain on capital account. Another Rs. 49 crores is accounted for by additional defence expenditure on revenue account. This is the result of increases granted during the year in allowances to certain categories of Service personnel, the dearness allowance which become due last September, the recent decision to merge a part of the dearness allowance with pay and speedier deliveries of stores against existing orders. On capital account, there has been a reduction in defence expenditure of Rs. 15 crores. Honourable Members would see that barring the increase under defence and transactions of a purely accounting nature, revenue expenditure has been held within less than 1 per cent margin of the Budget Estimates.
- 10. On capital account, the variations have been of a more substantial order. Net external assistance will show a shortfall of Rs. 121 crores and PL 480 and other food aid a shortfall of Rs. 43 crores. This would be offset to an extent by improvement under market loans, reduction in the provision for transactions in foodgrains and fertilizers and some shortfall in Plan outlays. There are also a number of variations in other items which make on balance for an improvement in the resources position.
- 11. In the aggregate, the budgetary deficit this year is now estimated at Rs. 260 crores as against Rs. 290 crores in the Budget Estimates. Honourable Members, I am sure, would not consider this 10 per cent variation in deficit financing as an index of conservative budgeting on my part.

Budget Estimates -1969-70

- 12. In the Budget Estimates for 1969-70, I have assumed that at existing rates of taxation, total revenues accruing to the Centre will increase by Rs. 151 crores I anticipate a further decline in customs receipts from Rs. 445 crores this year to Rs. 426 crores in 1969-70. This reduction is based on the expectation that while there would be some increase in total non-food imports, there would be a shift away from items such as petroleum products which bear duties at a higher rate. Union excise duties are expected to show an increase of Rs. 101 crores. Corporate and income taxes should yield Rs. 675 crores as against Rs. 660 crores this year. Non-tax revenues should also yield Rs. 50 crores more.
- 13. The increase in revenue will, however, be more than absorbed by increases in expenditure on revenue account. Defence expenditure on revenue account will be more by Rs. 42 crores. Excluding certain accounting adjustments, the non-Plan civil expenditure will be more by Rs. 142 crores. Of this Rs. 41 crores are accounted for by interest charges. The Fifth Finance Commission's recommendations have necessitated an additional devolution of Rs. 36 crores to the States. Committed expenditure arising out of completed Plan schemes has meant an increase of nearly Rs. 35 crores. Export promotion measures account for another increase of Rs. 10 crores. Various miscellaneous items, including administrative services, tax collection and assistance to neighbouring countries account for the rest of the increase. Detailed explanations have, as usual, been given in the Explanatory Memorandum.
- 14. On capital account, net market borrowings next year are estimated at Rs. 106 crores as against Rs. 81 crores this year. Small savings are placed at Rs. 135 crores i.e.. Rs. 10 crores more, but of this nearly two-thirds will accrue to the States. The Public Provident Fund should yield Rs. 5 crores next year as against Rs. 2 crores this year. On the other hand, as the author of the once famous but now almost forgotten Compulsory Deposit Scheme, I propose to redeem myself by making full provision of Rs. 25 crores for the repayment of the deposits made in 1963-64.
- 15. Net external aid, excluding PL 480 and other food aid, should show a marginal increase from Rs. 459 crores this year to Rs. 467 crores in 1969-70. While debt repayments would be larger, we expect an increase in aid disbursements also mainly as a result of resumption of aid by the International Development Association
- 16. In December 1968 we signed an agreement with the United States Government under PL 480 for the import of 2.3 million tonnes of foodgrains. In addition, we have continued to receive food assistance of a sizeable order from Canada as also some assistance under the International Grain Arrangement from Australia

- and the U.K. A substantial part of the food assistance thus negotiated will result in imports only next year. Honourable Members would also appreciate that arrangements for the concessional imports of foodgrains and agricultural raw materials will be necessary for some more time. Consequently, the net budgetary support accruing as a result of PL 480 transactions and other food aid, excluding PL 480 grants already accounted for in the revenue estimates, is placed at Rs. 224 crores next year as against Rs. 226 crores this year.
- 17. The improvements under internal borrowing and external assistance, just mentioned, i.e., Rs. 13 crores in all, will be more than absorbed by the increase in defence expenditure on capital account. Rs. 17 crores and on border roads, Rs. 4 crores.
- 18. As regards other capital transactions, the food and fertilizer transactions together show an improvement of Rs. 76 crores. Total stocks of foodgrains with the Food Corporation at the end of March 1969 should be of the order of 3.5 million tonnes. During the coming year, we propose to add another 1.5 million tonnes to these stocks. It is our intention to provide budgetary resources of Rs. 25 crores in 1969-70 for this purpose. The balance of the requirements will be provided by way of accommodation to the Food Corporation from commercial banks.
- 19. The improvement under foodgrains and fertilizer transactions, however, will be wiped out by the increases in revenue and capital expenditure already mentioned and worsening under various miscellaneous debt-deposit heads. I have also had to provide for some relief to States by way of adjustment in the repayments to the Centre and assistance towards the non-Plan gaps of some of the States to enable them to undertake a satisfactory Plan next year. In the net, the resources available, at the existing rates of taxation and on the basis of the likely availability of internal borrowing and external assistance, leave practically no margin for increasing the provision for the Plan to be financed through the Centre's Budget next year.
- 20. The budgetary contribution of public sector undertakings next year is also not likely to show any significant improvement over the current year. The question of better functioning of public sector undertakings has been examined in detail by the Administrative Reforms Commission as well as by the Bureau of Public Enterprises. Government have already taken a number of decisions to improve the working of these enterprises and I am separately circulating a memorandum on this subject to Honourable Members.
- 21. Honourable Members may well ask whether the margin of resources available for the Plan could not have been increased by economies in non-Plan expenditure. I have given the most careful thought to this question in framing the expenditure estimates for the coming year. But Honourable Members would appreciate that a certain increase in non-Plan expenditure is inevitable as it arises from contractual obligations or decisions already taken. The transfer of completed Plan schemes to the non-Plan side, interest charges, export promotion, the incidence of dearness allowance, the merger of dearness allowance with pay and the recommendations of the Finance Commission which belong to this category account for the bulk of the increase in civil expenditure. The increase of Rs. 59 crores in defence expenditure is explained mainly by normal increases in salaries and pensions, the additional dearness allowance which became due last September, merger of dearness allowance with pay, additional equity investment in the production units under the charge of the Defence Ministry and larger deliveries against contracts already entered into.
- 22. I should perhaps also say a word at this stage about the scope for deficit financing next year. This scope cannot be defined in terms of the needs of the Budget. It has to be determined in relation to the needs of the economy in the light of the likely growth in production and the saving habis of the people. Taking everything into account, I have come to the conclusion that a budgetary deficit next year of roughly the same magnitude as this year is likely to reconcile best the concern for price stability and the maintenance of a climate for growth.
- 23. It is against this background that I come now to my proposals for resource mobilization for the coming year. In framing these proposals, however, I have not adopted the simple approach of deciding first on a certain desired level of Plan outlay and of proceeding then to raise resources on the required scale. There are limits beyond which resources cannot be raised in the short-run without impairing the functioning of the economy. Equally, the annual Budget has to take into account not only the needs of the year but the requirements of long-term

growth as well. The approach, in other words, has to be one of making such changes in the tax structure as are necessary and leasible to build up the ability of the Government—and even more important of the economy in general—to sustain progressively larger developmental outlays and of limiting the expenditure proposals in the short-run to the total resources that can be so mobilised.

- 24. Honourable Members would now naturally be anxious to see how well I measure up to my own standards I hope that in passing judgement, the customary indulgence towards Finance Ministers will not be defined to me merely pecause this predicament of being held up before my own mirror is not altogether unfamiliar to me in this Honourable House.
 - 25. Broadly speaking, my tax proposals are intended:
 - (a) to provide a measure of relief where necessary, particularly in the interest of exports, savings and modernisation of key industries;
 - (b) to remove anomalies;
 - (c) to provide a further measure of rationalisation and simplification;
 - (d) to plug the loopholes which make for tax avoidance or evasion;
 - (e) to spread the burden of taxation more evenly by bringing within the tax net commodities or incomes which are hitherto not taxed or taxed lightly in relation to essentiality of consumption or capacity to pay; and
 - (f) generally, to make the tax system more responsive to the needs of economic growth.

Before Honourable Members conclude that I am about to serve them a rich fare, I should reassure them that I propose to bring up my appetizers at suitable intervals. I shall also concentrate on the main courses, leaving the sundries to be discovered in the Explanatory Memorandum.

Customs Duties

- 26. To begin with, an export offering to propitiate the gods of international competition. I propose to reduce the export duty on jute hessian from Rs. 500 per tonne to Rs. 200 per tonne. The duty on jute sacking is also proposed to be reduced from Rs. 250 per tonne to Rs. 150 per tonne, while the duty on wool sacks and cotton bagging is being completely exempted. The export duty on tea is being reduced from 20 per cent less 35 paise per kilogram to 15 per cent less 55 paise per kilogram. The duty on degreased raw wool and on package tea in metal containers is being completely exempted while the duty on package tea in other containers is being reduced from 15 per cent to 5 per cent. The export duty on mica is proposed to be reduced from 40 per cent to 20 per cent in respect of loose splittings of smaller size. The total effect of these reductions will be a loss in revenues of Rs. 23 crores per year.
- 27. Generally, we levy an import duty of 100 per cent ad valorem on all items of luxury. The duty on imported motor cars is 60 per cent. I propose to improve the value of imported motor cars as a status symbol by increasing the duty to 100 per cent. In the case of dry fruits, the present valuation for calculating the duty is unrealistic. I propose to adopt a more realistic basis for valuation which will have the effect of raising the duty realisation. The import duty on lubricating oil is being raised from 15 per cent to $27\frac{1}{2}$ per cent to bring it in line with the duty on their constant companion, viz., machinery, and to give an edge to their domestic rivals. These changes will bring in a revenue of Rs. 6.2 crores.
- 28. We levy a countervailing import duty whenever a commodity is subject to excise. We also have power to levy a countervailing duty in lieu of the excise on the raw materials and components used in any excisable item. No such power exists when the commodity itself is not excisable. I propose to take power to remedy this omission, in the interest of import substitution. In certain cases such as bearings, ship stores and imports by post or air for personal use, multiplicity of rates or classification depending on use causes unnecessary delay and annoyance; and I propose to rectify this also.

Excise Duties

- 29. Coming to Excise Duties, it is now generally recognised that ad valorem duties are more rational than specific duties whose incidence declines during periods of rising prices and increases when prices fall. Ad valorem duties can also act as a spur to reduction in costs and prices. I propose, therefore, to convert the existing specific rates into ad valorem rates for cement, vegetable products, electric fans, lighting bulbs and tubes, soaps, soda ash, caustic seda and sodium silicate. Despite the necessity of rounding, I have resisted the temptation of collecting in the process any appreciable crumbs for the Exchequer.
- 30. But every rule has an exception; and I have been helped by one special circumstance in deciding on the exception to prove this particular rule. In the case of sugar, we have now a price for controlled releases and a free market price. The incidence of the present specific duty when converted into an ad valorem rate, would obviously give two different rates. In choosing between the two rates, I have shown some partiality for the controlled releases on which the present basic and additional duties work out approximately to an ad valorem rate of 23 per cent on an average. I have applied this rate to all crystal sugar. As a result, there will be no change in the average price of controlled sugar with only marginal variations in the different zones. Correspondingly, the duty on khandsari is proposed at 12½ per cent ad valorem with suitable revisions in existing compounding rates. I hope Honourable Members would not object to free market sugar being taxed at the same ad valorem rate as controlled sugar merely because it has the incidental effect of an additional revenue of Rs. 27.45
- 31. I propose to levy an excise duty at the rate of 10 per cent ad valorem on specific domestic electrical appliances and processed food. Honourable Members will recall that last year a duty at the rate of one paisa each was imposed on crown corks. I propose now to unite kings and commoners by an extension of the levy to other similar devices for covering bottles and containers. The levies on electrical appliances processed food and pilfer-proof caps will bring in a revenue of Rs. 4.0 crores.
- 32. Honourable Members would agree that those who benefit by our substantial investments in agriculture, including research, irrigation facilities, fertilizer plants, rural electrification, credit facilities and support prices should contribute a part of their prosperity towards the cost of development in general. This is all the more so when the benefit of improved technology cannot yet be shared by the majority of our farmers, particularly in dry regions where fertilizers and new seeds are not easy to apply. Similarly, the facilities for lift irrigation by power driven pumps are not spread uniformly. If the benefits of the new agricultural technology are to be carried progressively to a growing proportion of our farming population, the resources needed for this purpose should come at least in part from the beneficiaries of the process. Against this background, I propose to levy an excise duty of 10 per cent ad valorem on fertilizers and 20 per cent ad valorem on power driven pumps with a revenue yield of Rs. 24.0 crores of which Rs. 22 crores would be in respect of fertilizers.
- 33. It is obviously time now for me to turn to appetizers once again. As Honourable Members are aware, the cotton textile industry is going through a difficult time. Some relief in the excise duty is, therefore, called for. The excise duty on yarn in the form of hanks of plain straight reels is being abolished in respect of certain counts and lowered in respect of certain other counts. This should benefit the handloom sector. The powerloom sector will benefit by the abolition of the differential duty on sizing even though the duty on unsized yarn of some counts in the fine and superfine category is being increased. Further, duty on grey fabric is proposed to be abolished and the processing surcharges reduced by five paise per square metre on all varieties of Medium A and non-controlled Medium B and coarse categories of fabrics. This relief would very substantially benefit the weaker cotton mills. The total effect of all the relief proposed will be about Rs. 15.30 crores.
- 34. About 9.5 crores of the loss would, however, be made up by levying a higher duty of 5 palse per square metre on superfine and fine and 2.5 palse per square metre on all other categories of printed fabrics except the controlled ones and by selectively levying an ad valorem duty of 15 per cent on costlier variety of fabrics such as suitings, tapestry and furnishing fabrics, turkish towels and

others which at present bear a low incidence of duty in relation to their price. In addition, I propose to double the existing compounded levy on powerloom fabrics and to rationalise the duty structure on tents.

- 35. The duty on nylon yarn in the lower denicts is being reduced and this would be compensated to some extent by an increase in some of the higher ones. The net effect will be a drop in revenue of Rs. 3.5 cropps. This concession should help towards eliminating smuggling of nylon yarn about which there has been genuine concern.
- 36. The duty on confectionery, but not on chocolates, is being reduced from 80 paise per kilogram to 30 paise per kilogram. The duty on electronic valves, transistors and semi-conductor diodes used as components by radio manufacturers is being halved. Low priced sets manufactured by the larger manufacturers in the organised sector will, however, bear a duty of Rs. 10 per set. In the case of steel ingots and products manufactured out of scrap by electric furnace owners, I propose exemption to the extent of the ingot duty. The duty on embroidery, which is proving rather heavy, is being reduced. I am assured on good authority that in the topsy-turvy world of the cinema, the highest achievements of subtlety belong to those who are accustomed to think in terms of black and white. Accordingly, I propose to give some relief to the black and white cinematograph films and raise the incidence on colour films. I also propose to levy a nominal duty of two paise per metre on unexposed cinema films. The overall effect of the somewhat mixed bag of concessions on confectionery, component parts of radios, scrap based steel ingots, embroidery and cinema films will be a revenue loss of Rs. 3.13 crores.
- 37. To return to more familiar ground, I think the time has come when some of the old faithfuls of indirect taxation everywhere such as cigarettes and motor spirit are relieved of their annual agony. One way of achieving this is to raise the duties sufficiently. I must confess that I did not do a neat enough job in this regard in my last two Budgets. Accordingly, I propose to increase the duty on motor spirit by 7 paise per litre and on eightestes by 6 per cent to 18 per cent ad valorem in the different value slabs with a revenue of Rs. 29.84 crores. The duty on superior kerosene, which is being increasingly used as an adulterant for motor fuels, is also being raised by 4 paise per litre with a yield of Rs. 14.40 crores.
- 38. The basic excise duty on jute manufacturers is being raised by Rs. 100 per tonne so as to yield a revenue of Rs. 4.95 crores. The duty on cellulosic and non-cellulosic staple fibres is being raised by 20 paise per kilogram and Rs. 12 per kilogram respectively. The duty on rayon yarn is also being raised by about 10 per cent of the existing rates in all except the industrial deniers and the margin of concession in the rates of duty available to small producers compared to large producers of rayon yarn is being reduced. These proposals on synthetic fibres and yarn will yield an additional revenue of Rs. 9.37 crores annually. It is also my intention to transfer the duty on woollen yarn to wool tops; and to begin with, I am levying a small duty on wool tops with a yield of Rs. 6 lakks.
- 39. The cumulative effect of all the proposals relating to excise duties including a few sundries will be an additional revenue of Rs. 104.57 crores in a full year of which Rs. 79.95 crores will go to the Centre and Rs. 24.62 crores will be the States' share. As a result of the proposals relating to excise duties, there will be an additional yield of Rs. 26 crores on account of countervailing duty most notably on fertilizer imports.
- 40. The scheme of self-assessment and removal introduced since June 1968 has worked well and I propose to extend it as soon as possible to most excisable commodities.

Direct Taxation

41. In regard to corporate taxation, I propose to extend the tax holiday concession for new industrial undertakings and ships for a further period of five years from April 1, 1971 to March 31, 1976. I have also come to the conclusion that the familiar instrument of development rebate need not be abandoned or replaced by fancier alternatives. Accordingly, the development rebate will continue to be admissible, but in respect of machinery and plant installed after 31st March, 1970 the reduced rates already provided in the law will apply. The ceiling in the Companies (Profits) Surtax Act on the aggregate corporation tax payable by a widely-held domestic company at 70 per cent of its total income

has now become meaningless. But it still continues to mislead people as if the virtually non-operative ceiling is the norm. Accordingly, I propose to do away with this ceiling. Public companies whose shares are listed in a recognised Stock Exchange in India will now be treated as widely-held companies.

- 42. In order to minimise the repetitive import of technology and indeed to encourage the development of local know-how, I propose to tax income derived by Indian companies from the transfer or servicing of such know-how on a concessional basis. To encourage the modernisation of two of our important export industries, viz., cotton and jute textiles, I propose to include them in the list of priority industries for the purpose of the development rebate.
- 43. I propose to introduce later this Session a comprehensive Bill to amend the Income Tax Act and other related enactments. In that Bill, I intend to provide for amortization, over a 10-year period, of promotional expenses and expenses on project report, market surveys, etc. in the case of Indian companies, which are not at present eligible for any depreciation allowance or other deduction. The amount to be amortized will be limited to $2\frac{1}{2}$ per cent of the project cost. The classification of different items of machinery, for the purposes of depreciation, is also being considerably simplified, and the general rate for plant and machinery is being raised from 7 per cent to 10 per cent.
- 44. In order to bring about a smoother progression in the tax rates on personal incomes, I propose to make a marginal increase in the rate of tax on incomes in the slab of Rs. 10,001 to Rs. 15,000 by 2 per cent from 15 per cent to 17 per cent, and on incomes in the slab of Rs. 15,001 to Rs. 20,000, by 3 per cent from 20 per cent to 23 per cent. The full effect of these increases will fall on tax-payers having incomes of Rs. 20,000 or more and, taken together with the surcharge of 10 per cent of the basic income-tax, the additional tax will amount in each such case to Rs. 275 per year. These changes are expected to yield, in a full year, an additional revenue of Rs. 13.82 crores.
- 45. I propose to simplify and rationalise the taxation of co-operative societies. In the case of registered firms, I propose to increase taxation slightly by introducing a new slab of income between Rs. 10,001 and Rs. 25,000 on which the rate of basic income-tax will be 4 per cent. This change will yield in a full year additional revenue of Rs. 4.32 crores.
- 46. I have a special word of cheer for authors, artists, playwrights, musicians and actors. In their case, 25 per cent of the professional income derived from a foreign source and received in India in foreign exchange will be deducted from taxable income. In case this creates apprehensions of cultural drain, I would remind Honourable Members that the best things in life are generally for export.
- 47. Honourable Members are aware that there has been renewed interest in the equity market on the part of genuine investors. In order to encourage this trend, I propose to raise the exemption from tax enjoyed by dividend incomes from Indian companies from Rs. 500 at present to Rs. 1,000 per year. This will bring investment in shares in Indian companies in line with investment in units of the Unit Trust. I also propose to extend the area of existing tax relief in respect of life insurance premiums.
- 48. Agricultural wealth has so far been exempt from wealth tax. This has encouraged purchase of such land by the richer professional and business classes. While this has often acted as a spur to greater productivity in agriculture, there is no case in equity for taxing other productive wealth but exempting wealth in the form of agricultural land. I am advised by the Attorney General that the Parliament is competent to legislate for the levy of wealth tax on agricultural wealth. Accordingly, I propose to provide in the Wealth Tax Act for the levy of wealth tax on the value of agricultural land including buildings situated on or in the immediate vicinity of such land. Standing crops, tools, implements and equipment such as tractors will, however, be exempt. Agricultural wealth will be added to other wealth for the purposes of the tax at the existing rates with effect from the assessment year 1970-71. This measure will yield additional revenue of Rs. 5 crores in a full year. But in view of what I have just said, there would be no revenue gain in the coming year. It is my intention to pass on the net proceeds of the revenue of wealth tax on agricultural property to the States as grants-in-aid. I shall however consider as to how genuine agriculturists can be exempted from the purview of this measure and will be moving the necessary amendment to the Finance Bill at the appropriate time.

- 49. I am proposing a number of changes in the scheme of advance tax payments so as to make it more effective and also to reduce the burden of compliance on small-income tax payers. I am also proposing certain changes in the scale of penalties under the Wealth Tax Act for failure to furnish returns of net wealth and to produce accounts, documents, etc. Another change proposed is meant to ensure the smooth working of the provision made last year for greater use of the banking system in making payments for business expenditure.
- 50. Honourable Members are aware that ordinarily it is not possible for individuals to escape taxation on their income by transferring their assets to their spouse or minor children. This is, however, often circumvented by use of the special provisions relating to taxation of a Hindu undivided family as a separate unit. I intend to close this loophole by making a suitable provision in the Amendment Bill.
- 51. Altogether, the changes in direct taxation that I have proposed will yield an additional revenue next year of Rs. 11 crores for the Centre and Rs. 2.5 crores for the States.

Posts and Telegraphs

52. The Posts and Telegraphs Department will again run into a deficit next year. It is, therefore, proposed to revise from dates to be notified certain telephone and telegraph tariffs based broadly on the recommendations of the Tariff Enquiry Committee. A memorandum showing the proposed changes is being circulated along with the Budget papers. The telephone rentals in the four principal cities of Bombay, Calcutta, Madras and Delhi as also for other exchanges will be raised. The Directory enquiry service, which was hitherto free, will be charged. The additional charge for Particular Person and Fixed Time trunk calls will now be uniformly 50 per cent of the basic charge. Increases are also proposed on greetings telegrams, multiple telegrams and telex and a few other services. These changes are expected to yield in a full year Rs. 646 crores, and would be just sufficient to cover the anticipated revenue deficit. The effect of these changes has been accounted for in reckoning the total internal resources of public undertakings.

Summing Up

- 53. To sum up, the net additional revenue accruing to the Centre next year from the measures of taxation I have proposed would be about Rs. 100 crores, of which Rs. 11 crores would be under direct taxes, Rs. 80 crores under excise duties and Rs. 9 crores under customs duties after allowing for the reduction of Rs. 23 crores in export duties. In addition, a sum of about Rs. 27 crores will accrue to the States.
- 54. I may now summarise the Centre's resources position for the next year. The total gross revenue, after taking into account the additional taxation measures, is estimated at Rs. 3,519 crores, of which Rs. 519 crores will accrue to the States leaving Rs. 3,000 crores for the Centre. Non-Plan expenditure on revenue account, including grants to States, interest charges and defence expenditure, is placed at Rs. 2,558 crores, leaving a non-Plan revenue surplus of Rs. 442 crores. Next year's market borrowing and external borrowing, net of repayments, are estimated at Rs. 106 crores and Rs. 691 crores respectively. After taking into account the transactions under miscellaneous debt deposit heads and after providing for non-Plan capital expenditure and loans, including buffer stock provision and cash losses of some public-sector undertakings, the resources on capital account will be Rs. 1.046 crores. The Centre's budgetary resources for the Plan are accordingly Rs. 1,738 crores, including Rs. 250 crores of deficit financing. In addition, the public-sector undertakings, including the Railways and Posts & Telegraphs, are expected to find Rs. 165 crores for the Plan out of their own resources. The total availability of resources for the Plan next year, exclusive of the States' resources, will thus be Rs. 1,903 crores. Of this Rs. 65 crores to the Union Territorics, leaving Rs. 1,223 crores for the Central Plan proper including the Centrally sponsored schemes.
- 55. Next year's Budget makes a total Plan provision of Rs. 1,738 crores of which Rs. 402 crores are in the revenue budget and Rs. 1,336 crores are in the capital budget. The provision on revenue account includes Rs. 185 crores as grants-in-aid for State Plan schemes, being 30 per cent of the block Central Plan assistance payable from next year as against an average of 20 to 25 per cent at

present. The rest of the Plan provision in the revenue budget is on account of Union Territories Plan as also Central Plan. The Centrally sponsored schemes account for a provision of Rs. 117 crores taking revenue and capital sections together.

56. The Central Plan next year makes a larger provision as compared to the current year for steel production, ports, petrochemicals, fertilizer plants, development of iron ore mines for export and copper and aluminium production. In the main, the increase in outlay reflects the higher tempo of activity on continuing schemes. Even so, it will give a fillip to industries engaged in construction activity and specially the engineering industries. It is also proposed to accelerate the programme of construction of storage for foodgrains. The institutional arrangements for agricultural credit, particularly for fertilizer distribution and rural electrification, are being strengthened with necessary budget support. Larger outlays have also been proposed for family planning.

57. Sir, I cannot emphasise too strongly that my tax proposals and the modest increase in Plan outlays next year should be considered against the background of the severe constraint on our resources. For the past few years, the surplus on revenue account has been declining. For the next year, a revenue deficit of Rs. 60 crores at existing rates of taxation is anticipated in the Centre's Budget. Even after the proposed measures of additional taxation, the deficit will be converted into a surplus of Rs. 40 crores only. On capital account, the position has not shown undue deterioration only because food assistance has been maintained at a high level due to spill-over of imports from this year to next year. As self-reliance in foodgrains is achieved, this resource will progressively dwindle; and if development outlays are not to be curtailed unduly, other measures of raising resources will have to be devised. Honourable Members will also appreciate that the all-pervasive objective of growth with social and political stability and increasing self-reliance cannot be achieved by budgetary policy alone. It will require the disciplined participation of every section of the community and every region of the country. Only so we can carry this great nation forward in the struggle against mass poverty which is as rewarding as it is arduous. I can only hope that the Budget I have had the honour to present makes a modest contribution towards this end.

Thank you.